



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 25 अप्रैल, 2018 ई0

बैशाख 05, 1940 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 211/XXXVI(3)/2018/28(1)/2018

देहरादून, 25 अप्रैल, 2018

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित ‘उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (संशोधन) विधेयक, 2018’ पर दिनांक 23 अप्रैल, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या: 23 वर्ष, 2018 के रूप में सर्व-साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910) (अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2002) (संशोधन) अधिनियम, 2018

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 23, सन, 2018)

संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 (सं०प्रा० अधिनियम संख्या 4 वर्ष 1910) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेतर संशोधन करने के लिए,

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

संक्षिप्त नाम 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रांत आबकारी विस्तार और अधिनियम, 1910) (अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2002) (संशोधन) अधिनियम, प्रारम्भ 2018 है।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगा।

(3) यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

धारा 3 का 2. संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम संख्या 4 संशोधन वर्ष 1910) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त), जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में -

(एक) खण्ड (12) को निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात:-

"(12) मादक भेषज-मादक भेषज का तात्पर्य निम्नलिखित से है:

स्वापक औषधि मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत घोषित स्वापक औषधि व पदार्थों से भिन्न भाग के पत्तों या उससे तैयार पेय या अन्य कोई मादक पिनक पदार्थ जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो;

(दो) खण्ड (16) को निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात:-

"विक्रय"- व्याकरण सम्बंधी परिवर्तनों सहित विक्रय में अनुज्ञप्ति के अधीन होटल, रेस्टोरेंट, क्लब एवं अधिसूचित स्थलों में शराब परोसने और उसके प्रदाय तथा दान स्वरूप अन्तरण से भिन्न कोई अन्तरण सम्मिलित है ;

(तीन) खण्ड (22) के पश्चात नये खण्ड क्रमशः (23), (24), (25), (26), (27) और (28) निम्नवत अंतःस्थापित कर दिये जायेंगे, अर्थात:-

(23) "होटल"- होटल का तात्पर्य ऐसे व्यवसायिक स्थापन या उसके भाग से है जो भुगतान के बदले यात्रियों एवं पर्यटकों को ठहरने, खाने एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध कराता है ;

(24) "क्लब"- क्लब का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से है जो कम्पनी अधिनियम, 2013 या उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत हो और जो अपने सदस्यों को उनके अंशदान के फलस्वरूप सुविधायें या लाभ उपलब्ध कराता है ;

(25) "रेस्टोरेंट"- रेस्टोरेंट का तात्पर्य ऐसे व्यवसायिक स्थापन से है, जहां भोजन तैयार किया जाता है और ग्राहकों को भुगतान के बदले परोसा और उपलब्ध कराया जाता है ;

स्पष्टीकरण— उत्तर प्रदेश रेस्टोरेन्ट मदिरा उपभोग नियमावली-1952 (उत्तराखण्ड में यथा अनुकूलित एवं उपान्तरित) में दी गई रेस्टोरेन्ट की परिभाषा उक्त परिभाषा होने के बावजूद सम्बन्धित प्रयोजन हेतु यथावत् लागू रहेगी।

(26) "अधिसूचित स्थान" अधिसूचित स्थान से कोई भवन या किसी भवन का भाग और उसके संबद्ध परिसर तथा कोई भी विनिर्दिष्टतः सीमांकित भूमि अभिप्रेत है, जिसमें ऐसे अधिसूचित स्थान के भीतर उपयोग हेतु किसी अनुज्ञप्ति के निबन्धनों के अनुसार शराब का प्रदाय अनुज्ञात है ;

(27) "शराब परोसना और उसका प्रदाय" से अनुज्ञप्ति, जो इस शर्त पर जारी की जाती है कि ऐसी शराब का उपभोग ऐसे होटल, क्लब, रेस्टोरेन्ट एवं अन्य अधिसूचित स्थान के परिसर के भीतर किया जाएगा, के आधार पर क्लबों, रेस्टोरेन्ट, होटलों और किसी अन्य अधिसूचित स्थान पर प्रतिफलार्थ शराब उपलब्ध करवाना अभिप्रेत है ;

(28) "शराब की दुकान" शराब की दुकान से तात्पर्य शराब की ऐसी फुटकर दुकान से है, जिसको सील बन्द बोतल आदि में फुटकर शराब विक्रय की अनुज्ञप्ति प्राप्त हो ;

धारा 17 का 3.
संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्—

"(1) सिवाय कलैक्टर द्वारा तदर्थ दिये गये लाईसेन्स के प्राधिकार और उसके निबन्धनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए—

(क) कोई भी (मादक वस्तु) निर्मित न की जायेगी;

(ख) भांग के पौधे (कैनेबिस सैटाइवा) के किसी भी ऐसे भाग का जिससे कोई मादक भेषज निर्मित किया जा सकता हो, संग्रह न किया जायेगा,

(ग) विक्रय के लिये किसी भी शराब की बोतलों में बन्द न किया जायेगा, और

(घ) कोई भी व्यक्ति ताड़ी से भिन्न किसी (मादक वस्तु) के निर्माण के लिये किसी प्रकार के सामान, भभका, बर्तन, औजार या उपकरण का न तो प्रयोग करेगा, न अपने पास या न कब्जे में रखेगा।"

24-क का 4.
संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 24-क में—

(एक) उपधारा (1) तथा (2) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्—

"(1) धारा 31 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, आबकारी आयुक्त किसी व्यक्ति को किसी क्षेत्र में किसी विदेशी शराब का—

(क) निर्माण करने या थोक सम्भरण करने, या दोनों ही के लिये, या

(ख) फुटकर बिक्री के लिये, या

(ग) थोक बिक्री के लिये, या

(घ) दुकानों पर फुटकर बिक्री के लिए, एकान्तिक या अन्य विशेषाधिकार के लिये लाईसेंस या लाईसेंसों को स्वीकृत कर सकता है।

(2) किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में उपधारा (1) के खण्ड (घ) अधीन कोई लाईसेंस या लाईसेंसों के स्वीकृत किये जाने से उसी क्षेत्र में होटलों, रेस्टोरेन्टों, क्लबों एवं अधिसूचित स्थलों में उनके ही भू-गृहादि में उपभोग के निमित्त विदेशी शराब परोसने एवं प्रदाय के लिये लाईसेंस के स्वीकृत किये जाने पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।"

(दो) उपधारा (4) के पश्चात कमशः नई उपधाराएं (5) और (6) अंतःस्थापित कर दी जायेंगी, अर्थात्—

“(5) शराब परोसने और उसके प्रदाय सम्बन्धी एकांतिक विशेषाधिकारः होटल, रेस्टोरेन्ट, क्लब एवं अधिसूचित स्थलों के परिसरों में उपभोग हेतु शराब परोसने और उसके प्रदाय हेतु अनुज्ञप्ति जारी की जा सकेगी। किसी बात के होते हुए भी अनुज्ञप्ति धारण करने वाले प्रत्येक होटल, क्लब, रेस्टोरेन्ट या अधिसूचित स्थल के परिसरों के भीतर उसके सदस्यों, अतिथियों या अन्य व्यक्तियों को, यह विचार किये बिना कि ऐसा होटल, क्लब, रेस्टोरेन्ट या अधिसूचित स्थल किसी राज्य या राष्ट्रीय राजमार्ग पर या उसके निकट अवस्थित है, में उपयोग हेतु ऐसी शराब परोसने और उसका प्रदाय करने का हकदार होगा ; परन्तु यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्तिगत स्थान पर शराब को परोसने हेतु अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त कर लेता है तो ऐसा स्थान इस धारा के प्रयोजन के लिए अधिसूचित स्थान समझा जायेगा।

(6) किसी बात के होते हुए भी, किसी होटल, क्लब, रेस्टोरेन्ट या अन्य अधिसूचित स्थान को शराब के विक्रय हेतु जारी की गई अनुज्ञप्ति, शराब परोसने एवं उसका प्रदाय करने के लिए जारी की गई और सदैव जारी की गई समझी जायेगी और इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के समस्त सुसंगत उपबन्ध ऐसे लागू रहेंगे जैसे कि वे शराब के विक्रय हेतु लागू थे।

स्पष्टीकरणः—शंका के निराकरण हेतु यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि शराब के विक्रय के लिए यथा लागू समस्त कर, शुल्क, उपकर या अन्य उदग्रहण शराब को परोसने या उसका प्रदाय करने हेतु तब तक लागू होंगे जब तक किसी अन्य अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियम या अधिसूचना में अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए।”

धारा 36 का 5.
संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 36 को शीर्षक सहित निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्—

“फुटकर बिक्री या शराब परोसने और उसके प्रदाय सम्बन्धी लाईसेंस का समर्पण—

इस अधिनियम के अधीन फुटकर बिक्री या शराब परोसने और उसके प्रदाय सम्बन्धित किसी लाईसेंस का धारक लाईसेंस समर्पित करने के अपने अभिप्राय की अपने द्वारा कलेक्टर को दिये गये एक माह की लिखित नोटिस की अवधि व्यतीत हो जाने पर और उस सम्पूर्ण अवधि के लिये जिसमें लाईसेंस जारी रहता, यदि ऐसा समर्पण न कर दिया गया होता, लाईसेंस के निमित्त देय फीस भुगतान करने पर अपना लाईसेंस समर्पित कर सकता है;

प्रतिबन्ध यह है कि यदि आबकारी आयुक्त को यह समाधान हो जाय कि ऐसा लाईसेंस समर्पित करने के लिये पर्याप्त कारण है, तो वह समर्पण कर दिये जाने पर इस प्रकार देय धनराशि या उसका कोई अंश उसके धारक को प्रेषित कर सकता है।

स्पष्टीकरण— इस धारा में प्रयुक्त शब्द “लाईसेन्स का धारक” में वह व्यक्ति भी सम्मिलित है जिसका लाईसेन्स के निमित्त टेन्डर या बोली स्वीकार हो चुकी हो, यद्यपि उसे वास्तव में लाईसेन्स प्राप्त न हुआ है।

धारा 41 का 8.
संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 41 के खण्ड (क), (ख) और (ग) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे, अर्थात्—

“(क) किसी (मादक वस्तु) के निर्माण, सम्भरण, भण्डारकरण, परोसने या विक्रय को, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है, विनियमित करना—

(1) ऐसे पदार्थ के निर्माण, सम्भरण, भण्डारकरण या विक्रय के लिये किसी स्थान का

परिनिर्माण करना, उसमें परिवर्तन करना, उसकी मरम्मत करना, उसका निरीक्षण, पर्यवेक्षण, प्रबन्ध करना और उस पर नियन्त्रण रखना तथा उसमें अनुरक्षित किये जाने वाले उपस्कर, औजार और उपकरण,

(2) भांग के पौधे (कैनविस सेटाइवा) के उन भागों का संग्रहण करना जिनसे कोई मादक भेषज निर्मित किया जा सकता हो और उनसे किसी मादक भेषज का निर्माण करना,

(ख) किसी (मादक वस्तु) को भान्डागार में जमा किये जाने को और किसी ऐसे भान्डागार से या किसी आसवनी या यवासवनी से किसी (मादक वस्तु) के हटाये जाने को विनियमित करना।

(ग) किसी मादक वस्तु के किसी लाइसेन्स, परमिट या पास के लिये, जिसमें धारा 24 या धारा 24 क के अधीन किसी एकात्मिक या अन्य विशेषाधिकार के लिए दिया गया कोई प्रतिफल भी सम्मिलित है, या उसके भण्डारकरण के लिये देय फीस का माप-यान या उसे निश्चित करने की रीति विहित करना,

प्रतिबन्ध यह है कि इस खण्ड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह राज्य सरकार को समय-समय पर अधिसूचना द्वारा कोई ऐसा विशेषाधिकार स्वीकृत किये जाने के प्रतिफल के भाग के रूप में कोई फीस, जिनके अन्तर्गत विक्रय (वेन्ड) फीस भी है, लगाने से रोकती है।

स्पष्टीकरण— (1) विभिन्न वर्गों के लाइसेन्स, परमिट, पास या भण्डारकरण के लिये, और विभिन्न क्षेत्रों के लिए इस उपखण्ड के अधीन फीस विभिन्न दरों पर विहित की जा सकती है।

(2) ऐसी फीस या प्रतिफल निश्चित करने की रीति के अन्तर्गत निम्नलिखित कोई एक या अधिक रीति भी है, अर्थात्—

- (1) नीलाम,
- (2) टेन्डर आमन्त्रित करना,
- (3) लाइसेन्स, परमिट या पास के अधीन किये गये विक्रय या उठाये गये कोटा के आधार पर निर्धारण।
- (4) उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कोई व्यवस्था।

धारा 60 का 7.
संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 60 की उपधारा (1) को निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्—

“(1) जो व्यक्ति इस अधिनियम का या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये किसी आदेश का या इसके अधीन प्राप्त किसी लाइसेन्स, परमिट या पास का उल्लंघन करके—

(क) किसी मादक वस्तु का आयात, निर्यात या परिवहन करता है या उसको अपने कब्जे में रखता है, या

(ख) भांग (कैनविस सेटाइवा) के किसी ऐसे भाग का संग्रह या विक्रय करता है जिससे कोई मादक भेषज निर्मित किया जा सकता है, या

(ग) कोई आसवनी, यवासनी या द्राक्षासवनी निर्मित करता है या चलाता है, या

(घ) किसी प्रकार का कोई सामान, भभका, बर्तन, औजार या उपकरण ताड़ी से भिन्न किसी मादक वस्तु के निर्माण के लिये प्रयुक्त करता है या अपने पास या अपने कब्जे में रखता है, या

(ङ) इस अधिनियम के अधीन लाइसेन्स प्राप्त, स्थापित या चालू किसी आसवनी, यवासनी, द्राक्षासवनी या भण्डारगार से कोई मादक वस्तु हटाता है, या

(च) विक्रय के लिये किसी शराब की बोतल में बन्द करता है, या

(छ) धारा 61 में व्यवस्थित दशा के सिवाय किसी मादक वस्तु का विक्रय करता है, या

(ज) धारा 42 के अधीन अधिसूचित क्षेत्रों में ताड़ी पैदा करने वाले वृक्षों से ताड़ी चुआता है, या निकालता है, तो उसे कारावास का दण्ड दिया जायेगा जो दो वर्ष तक हो सकता है और अर्धदण्ड दिया जायेगा जो खण्ड (झ) के अधीन अपराध की स्थिति में

ऐसी उत्पाद शुल्क की धनराशि जो, यदि ऐसी मादक वस्तु के सम्बन्ध में इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों और दिये गये आदेशों के अनुसार या इसके अधीन प्राप्त लाईसेन्स, परमिट या पास के अनुसार कार्यवाही की गयी होती तो उदग्रहणीय होती, के दस गुने से कम न होगा और किसी अन्य स्थिति में ऐसे उत्पाद-शुल्क की राशि के दस गुने या पाँच हजार रुपये से, जो भी अधिक हो, कम न होगा।"

धारा 61 का 8.
संशोधन

धारा 61 के खण्ड (क) तथा (ख) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्—

"(क) धारा 22 का उल्लंघन करके कोई शराब या मादक भेषज किसी ऐसे व्यक्ति को बेचता है या जो स्पष्टतः 21 वर्ष से कम आयु का हो, या

"(ख) धारा 23 का उल्लंघन करके अपने लाईसेंस प्राप्त भू-गृहादि के किसी भाग में जिसका उल्लेख उक्त धारा में किया गया है, 21 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति, को या किसी महिला की सेवायोजन में रखता है अथवा सेवायोजन करने की अनुज्ञा देता है, तो उसे अर्थ दण्ड दिया जायेगा जो दस हजार रुपये तक हो सकता है।"

धारा 62 का 9.
संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 62 को शीर्षक सहित निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्—

"विकृत स्प्रिट की मानव उपयोग के योग्य बनाने के लिए शास्ति:

जो कोई किसी ऐसी स्प्रिट को, चाहे वह भारत में निर्मित हुई हो या नहीं, जो विकृत हो गयी हो, मानव उपयोग के योग्य बनाता है बनाने का प्रयास करता है या कब्जे में कोई ऐसी विकृत स्प्रिट रखता है जो मानव उपभोग के योग्य बनायी गयी हो या जिसके सम्बन्ध में उसे इस योग्य बनाने का कोई प्रयास किया गया हो उसे ऐसी अवधि के लिए जो छः मास से कम नहीं होगी और जो तीन वर्ष तक हो सकती है, कारावास का दण्ड दिया जायगा और वह अर्थदण्ड जो पाँच हजार से कम न हो और जिसे पचास हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, से दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनार्थ यह उपधारणा की जायगी कि कोई स्प्रिट जिसके बारे में यह साबित हो जाय कि जिसमें किसी मात्रा में विचारक तत्व है, विकृत स्प्रिट है या उसमें विकृत स्प्रिट मिला है या वह विकृत स्प्रिट से व्युत्पन्न है।"

धारा 63 का 10.
संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 63 को शीर्षक सहित निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्—

"अवैध रूप से आयात की गई मादक वस्तु, आदि को कब्जे में रखने के लिए शास्ति:

जो कोई व्यक्ति बिना वैध प्राधिकार के कोई (मादक वस्तु) किसी परिमाण में अपने कब्जे में यह जानते हुए अवैध रूप से आयात किया गया है, उसका परिवहन किया गया है या उसे निर्मित किया गया है या यह जानते हुए कि उस पर विहित उत्पाद-शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है, रखे तो उसे ऐसी अवधि के लिए कारावास का दण्ड दिया जायगा जो (एक वर्ष) तक हो सकता है अथवा अर्थदण्ड दिया जाएगा जो मादक वस्तु से प्राप्त होने वाले उत्पाद-शुल्क के दस गुना या पाँच हजार रुपये से, जो भी अधिक हो से कम न होगा या दोनों दण्ड दिये जायेंगे।"

धारा 64 का 11.
संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 64 को शीर्षक सहित निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्—

"लाईसेंसधारी या उसके सेवक द्वारा कतिपय कार्यों के लिए शास्ति— जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी लाईसेन्स, परमिट या पास का धारक होते हुए या ऐसे धारक के सेवायोजन में होते हुए और उसकी ओर से कार्य करते हुए—

(क) किसी आबकारी अधिकारी द्वारा माँगे जाने पर या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा माँगे जाने पर, जो इस प्रकार माँगने के लिए सम्यक् रूप के अधिकृत हो, ऐसा लाईसेन्स, परमिट या पास प्रस्तुत नहीं करता है या

(ख) लाईसेन्स, परमिट या पास की किन्हीं शर्तों का उल्लंघन करके जानबूझकर कोई ऐसा कार्य या कार्य-लोप करता है, जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्ध न हो, या

(ग) ऐसे मामले जिसके लिए धारा 60 में उपबन्ध है, से भिन्न किसी मामले में धारा 40 के अधीन बनाये गये किसी नियम का जानबूझकर उल्लंघन करता है, उसे प्रत्येक ऐसे उल्लंघन के लिए अधिकतम रू0 20,000/- अर्थदण्ड विहित जायेगा।"

धारा 64क का 12.
संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 64क को शीर्षक सहित निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्—

"लाईसेंस प्राप्त विक्रेता या निर्माता द्वारा अपमिश्रण आदि के लिए शास्ति—

(1) जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी मादक वस्तु के विक्रय या निर्माण के लिए लाईसेंस धारक होता हुए, या ऐसे धारक के सेवायोजन में होते हुए अपने द्वारा विक्रीत या निर्मित मादक वस्तु में कोई हानि-कारक भेषज या कोई अनुपयुक्त तत्व जिससे उसकी वास्तविक या आभाषित मादकता या सान्द्रता बढ़ने की सम्भावना हो, या इस अधिनियम के अधीन बनाये गए किसी नियम द्वारा निषिद्ध कोई पदार्थ मिलाता है या मिलाने की अनुज्ञा देता है तो जब ऐसा मिश्रण भारतीय दण्ड संहिता की धारा 272 के अधीन अपमिश्रण के अपराध की कोटि में न आता हो, उसे कारावास का दण्ड जो छः मास से कम न होगा और जो तीन वर्ष तक हो सकता है, और अर्थदण्ड भी, जो दस हजार रुपये से कम नहीं होगा और जो बीस हजार तक हो सकता है, दिया जायगा।

(2) जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी मादक वस्तु के विक्रय या निर्माण के लिए लाईसेंस धारक होता हुए या ऐसे धारक के सेवायोजन में होते हुए किसी ऐसी शराब जिसके बारे में वह जानता है या उसे विश्वास करने का कारण है कि वह देशी शराब है, विदेशी शराब के रूप में विक्रय करता है या विक्रयार्थ रखता या प्रदर्शित करता है, उसे कारावास का दण्ड जो तीन वर्ष तक हो सकता है, और अर्थ-दण्ड जो बीस हजार रुपये तक हो सकता है, दिया जायगा;

प्रतिबन्ध यह है कि दण्ड निम्नलिखित से कम न होगा—

(एक) प्रथम अपराध के लिए तीन मास का कारावास और दो हजार रूपयों का अर्थ-दण्ड, और

(दो) प्रत्येक द्वितीय अनुवर्ती अपराधों के लिए छः मास का कारावास और पांच हजार रुपये का अर्थ-दण्ड।"

धारा 65 का 13.
संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 65 को शीर्षक सहित निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्—

"केमिस्ट की दुकान, आदि में उपभोग के लिए शास्ति—

(1) यदि कोई केमिस्ट, औषधि विक्रेता, औषधि वैद्य या कोई औषधालय का रक्षक किसी ऐसी मादक वस्तु को जिसे यथार्थ रूप में औषधीय प्रयोजन के लिए औषधियुक्त न किया गया हो, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उसके व्यवसाय में सेवायोजित न हो, अपने व्यवसाय के भू-गृहादि में उपभोग किये जाने की अनुज्ञा देता है तो उसे ऐसी अवधि के लिए कारावास का दण्ड दिया जायेगा जो छः माह तक हो सकता है या अर्थदण्ड दिया जाएगा जो बीस हजार तक हो सकता है या दोनों दण्ड दिये जायेंगे।

(2) यदि कोई व्यक्ति जो पूर्ववत प्रकार से सेवायोजित न हो ऐसे भू-गृहादि में किसी ऐसी मादक वस्तु का उपभोग करता है तो उसे अर्थ-दण्ड दिया जायगा जो पाँच हजार रुपये तक हो सकता है।"

धारा 74 का 14.
संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 74 को शीर्षक सहित निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्—

"अपराधों का शमन :

(i) कोई आबकारी अधिकारी जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से

सशक्त किया गया हो किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका लाईसेंस, परमिट या पास धारा 34 के अधीन निरसित या निलम्बित किये जाने योग्य हो या जिसके सम्बन्ध में युक्तियुक्त सन्देह हो कि उसने धारा 64 या धारा 68 के अधीन दण्डनीय अपराध किया है, यथास्थिति ऐसे निरसन या निलम्बन के बदले में या किये गये अपराध के शमन के रूप में अधिकतम रू० 1,00,000/- (एक लाख मात्र) और ऐसे सभी मामलों में जिनमें इस अधिनियम के अधीन जब्त की जाने योग्य कोई सम्पत्ति अभिगृहीत की गयी हो, उस सम्पत्ति के (ऐसे अधिकारी द्वारा अनुमानित) मूल्य का भुगतान किये जाने पर उसे छोड़ सकता है।

(2) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त कोई अधिकारी राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए, अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात् जहाँ अन्तर्ग्रस्त मादक वस्तु का परिमाण राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित परिमाण से अधिक न हो, वहाँ धारा 60 की उपधारा (1) के खण्ड (क) या धारा-63 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का या धारा 60 की उपधारा (3) के अधीन दण्डनीय किसी भी अपराध को, प्रशमन शुल्क के रूप में ऐसी धनराशि जो पाँच हजार रुपये से कम नहीं होगी, भुगतान करने पर, प्रशमन कर सकता है; परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि न्यूनतम प्रशमन की धनराशि धारा 60(1), 60(3) एवं धारा 63 में उल्लेखित अर्थ-दण्ड से कम न होगी।

(3) ऐसे व्यक्ति द्वारा, यथास्थिति, ऐसी धनराशि या ऐसे मूल्य या दोनों का भुगतान कर दिये जाने पर उस व्यक्ति को, यदि अभिरक्षा में हो, निर्मुक्त कर दिया जायेगा और अभिगृहीत समस्त सम्पत्ति सिवाय मादक वस्तु के छोड़ दी जा सकेगी और ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किसी दण्ड न्यायालय में कोई कार्यवाही संस्थित नहीं की जायेगी न जारी रखी जायेगी। शमन के रूप में ऐसी धनराशि स्वीकार करने पर उसे दोषमुक्त समझा जायेगा और किसी भी स्थिति में ऐसे व्यक्ति या सम्पत्ति के विरुद्ध उसी कार्य के अभिदेश में कोई अग्रेत्तर कार्यवाही नहीं की जायेगी।"

धारा 74क का 15.
संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 74क को शीर्षक सहित निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्—

"शास्ति आरोपणः

(1) यदि इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी लाईसेंस, परमिट या पास का धारक या ऐसे धारक का कोई कर्मचारी लाईसेंस, परमिट या पास की किन्हीं शर्तों या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम का उल्लंघन करता है तो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई आबकारी अधिकारी अधिकतम रू० 1,00,000/- (एक लाख मात्र) की शास्ति आरोपित कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन शास्ति आरोपित करने का कोई आदेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि इस लाईसेंस, परमिट या पास के धारक या सम्बद्ध कर्मचारी को—

(क) उन अपराधों को जिन पर इस धारा के अधीन कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है, सूचित करते हुए लिखित नोटिस न दे दी गयी हो,

(ख) ऐसे समय के भीतर, जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाय, ऐसे आधार के विरुद्ध लिखित रूप में अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो, और

(ग) मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(3) कोई व्यक्ति जिस पर उपधारा (1) के अधीन शास्ति आरोपित की जाय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के सम्बन्ध में उन्हीं तथ्यों पर अभियोजित नहीं किया जा सकेगा।"

आज्ञा से.

मीना तिवारी,
प्रमुख सचिव।

No.211/XXXVI(3)/2018/28(1)/2018

Dated Dehradun, April 25, 2018

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of '**The Uttarakhand (The United Provinces Excise Act, 1910) (Adaptation and Modification Order, 2002) (Amendment) Act, 2018**' (Adhiniyam Sankhya: 23 of 2018).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 23 April, 2018.

The Uttarakhand (The United Provinces Excise Act, 1910) (Adaptation and Modification Order, 2002) (Amendment) Act, 2018

(Uttarakhand Act No. 23 of 2018)

An

Act

further to amend the United Provinces Excise Act, 1910 (UP Act no 4 of 1910) (as applicable to the State of Uttarakhand) to the context of the State of Uttarakhand,

Enacted by the Uttarakhand State Assembly in the Sixty-ninth Year of the Republic of India-

Short Title and Commencement 1. (1) This Act may be called the Uttarakhand (the U.P. Excise Act, 1910) (Adaptation and Modification Order, 2002) (Amendment) Act, 2018.

(2) It extends to the whole of Uttarakhand.

(3) It shall come into force at once.

Amendment of Section 3 2. In the United Provinces Excise Act, 1910 (UP Act no 4 of 1910) (as applicable to the State of Uttarakhand), hereinafter is referred to as the Principal Act, in Section 3-

(i) Clause (12) shall be substituted as follows, namely-

"(12) 'intoxicating drug' means following intoxicating drug, namely-

Narcotics drugs and substances, other than leaves of hemp or drink prepared by it or any other intoxicating substances declared under the Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, Act, 1985 which is notified by the State Government."

(ii) Clause (16) shall be substituted as follows, namely-

(16) "sale" with its grammatical variations includes any transfer other than by way of service of liquor and its service and by gift in the hotel, restaurant, club and notified places under the licence in sale;

(iii) New clauses (23),(24),(25),(26),(27) and (28) shall be inserted after Clause (22) as follows, namely -

(23) "Hotel" : means a commercial establishment or a part of a building where residential accommodation is, by way of business, provided for a monetary consideration;

(24) "Club" : means any person or body of persons, registered under the Company Act, 2013 or the Uttarakhand Co-operative Society Act, 2003 or Society Registration Act, 1860 providing services, facilities or advantages, primary to its members, for a subscription or any other amount;

(25) "Restaurant": means a commercial establishment where meals are prepared and served to customers for a monetary consideration.

Explanation: Definition of restaurant given in UP Restaurant Consumption of Liquor Rules, 1952 (as adopted and modified in the Uttarakhand), shall be applicable for relevant purposes in spite of the said definition.

(26) "Notified place": means any building or part of a building and the premises appurtenant thereto and any specifically demarcated land wherein the supply of liquor in terms of a licence is permitted for consumption within such notified place;

(27) "Service and supply of liquor": means providing of liquor for consideration at clubs, restaurants, hotels and any other notified place on the basis of licence issued on the condition that such liquor shall be consumed within the premises of such hotel, club, restaurant or other notified place;

(28) "Shop of liquor": means such retail shop who have licence of sale liquor in the sealed bottle etc. in retail."

Amendment of section 17 3.

Sub section (1) of section 17 of the Principle Act shall be substituted as follows, namely-

"(1) (a) No intoxicant shall be manufactured ;

(b) no portion of the hemp plant (*cannabis sativa*) from which any intoxicating drug can be manufactured shall be collected;

(c) no liquor shall be bottled for sale ; and

(d) no person shall use, keep or have in his possession any substantial, still, utensil, implement or apparatus whatsoever for the purpose of manufacturing any intoxicant other than *tari*.

Except under the authority and subject to the terms and conditions of a licence granted in that behalf by the Collector."

**Amendment of
section 24.A**

4. In Section 24.A of the Principle Act,-

(i) Sub-section (1) and (2) shall be substituted as follows, namely-

"(1) Subject to the provisions of section 31, the Excise Commissioner may grant to any person a licence or licences for the exclusive or other privilege -

(a) of manufacturing or of supply by wholesale, or of both; or

(b) selling by retail; or

(c) of selling by wholesale

(d) of selling by retail at shops

any foreign liquor in any locality.

(2) The grant of licence or licences under clause (d) of sub-section (1) in relation to any locality shall be without prejudice to the grant of licences for the retail sale of foreign liquor in the same locality in hotels, restaurants, clubs and notified places for consumption on their premises

(ii) New sub-section (5) and (6) shall be inserted after sub-section (4) as follows, namely-

"(5) **Exclusive privilege for service and supply of Liquor :** Licence may be granted for service and supply for consumption of liquor within the premises of hotel, restaurant, club and notified places. Every hotel, club, restaurant or any notified place having a licence shall be entitled to engage in the service and supply of liquor to members, guests or other persons for consumption of such liquor within the premises of such club, hotel, restaurant or notified place, irrespective of whether such club, hotel, restaurant or notified place, is located on or near any State or National Highway:

Provided that if any persons obtains permit for serving of liquor at a private place, then such place shall be considered as notified place for the purpose of this section.

(6) Any licence issued to any hotel, club, restaurant or other notified place for the sale of liquor shall be deemed to have been and always be deemed to have been issued for the service and supply of liquor and all relevant provisions of this Act and the rules made there under shall continue to apply as they did for sale of liquor.

Explanation- For the removal of doubt, it is hereby clarified that all taxes, duties, cess or other levies as applicable to sale of liquor shall apply to service and supply of liquor unless otherwise specified in this or any other Act, rule or notification made thereunder."

Amendment of
section 36

5.

Section 36 with title of Principle Act shall be substituted as follows, namely-

"Surrender of licence regarding retail sale or service and supply of liquor :

Any holder of a licence regarding retail sale or service and supply of liquor under this Act may surrender his licence on the expiration of one month's notice in writing given by him to the Collector of his intention to surrender the same and on payment of the fee payable for the licence for the whole period for which it would had been continued if such surrender not done ;

Provided that, if the Excise Commissioner is satisfied that there is sufficient reason for surrender such a licence, he may remit to the holder thereof the sum so payable on surrender, or any portion thereof.

Explanation- The words "holder of a licence" as used in this section, also include a person whose tender or bid for a licence has been accepted, although he may not actually have received the licence."

Amendment of
section 41

6.

Clauses (a),(b),(c) of section 41 in Principle Act shall be substituted as follows, namely-

"(a) regulating the manufacture, supply, storage or sale of any intoxicant including-

(i) the erection, alteration, repair, inspection, supervision, management and control of any place for the manufacture, supply, storage or sale of such article and the fittings implements and apparatus to be maintained therein ;

(ii) the collection of portions of the hemp plant (*cannabis sativa*) from which any intoxicating drug can be manufactured and the manufacture of any intoxicating drug therefrom;

(b) regulating the deposit of any intoxicant in a warehouse and the removal of any intoxicant from any such warehouse or from any distillery or brewery ;

(c) prescribing the scale of fees or manner of fixing, the fees payable for any licence, permit or pass including any consideration for the grant of any exclusive or other privilege granted under section 24 or section 24-A or for storing of any intoxicant ;

Provided that nothing contained in this clause shall be construed to prevent the State Government from levying any fee, including vend fee, as part of consideration for the granting of any such privilege by notification made from time to time.

Explanation—

(1) Fees may be prescribed under this sub-clause at different rates for different class of licences, permits, passes or storage and for different areas.

(2) The manner of fixing such fee or consideration includes any one or more of the following manners; namely-

- (i) auction,
- (ii) invitation of tenders,
- (iii) assessment on the basis of sales made or quota lifted under the licence, permit or pass;
- (iv) any other provision in addition to aforesaid.

Amendment of
section 60

7.

Sub-section (1) of section 60 in Principle Act shall be substituted as follows, namely -

“(1) Whoever, in contravention of this Act or of any rule or order made thereunder, or of any licence, permit or pass obtained thereunder -

- (a) imports, exports, transport or possesses any intoxicant; or
- (b) collects or sells any portion of the hemp plant (*cannabi sativa*) from which any intoxicating drug can be manufactured; or
- (c) constructs or runs any distillery, brewery or vintnery; or
- (d) uses, keeps or has in his possession any material, stills, utensil, implement or apparatus, whatsoever, for the purpose of manufacturing any intoxicant other than *tari*; or
- (e) removes any intoxicant from any distillery, brewery, vintnery or warehouse licensed, established or continued under this Act; or
- (f) bottles any liquor for purposes of sale; or
- (g) sells any intoxicant, save in the case provided in section 61; or
- (h) taps or draws *tari*, from any producing tree in the areas notified under section 42;

shall be punished with imprisonment which may extend to two years and with fine which shall, in the case of an offence under clause (i) not be less than ten times the amount of duty which would have been leviable if such intoxicant had been dealt with in accordance with this Act, and the rules and orders made thereunder or in accordance with any licence, permit or pass obtained thereunder, and in any other case, not be less than ten times the amount of such duty, or five thousand rupees, whichever is greater.

Amendment of
section 61

8.

Clauses (a) and (b) of section 61 in Principle Act shall be substituted as follows, namely-

“(a) in contravention of section 22 sells or delivers any liquor or intoxicating drug to any person apparently under the age of twenty one years; or

(b) in contravention of section 23 employs or permits to be employed on any part of his licensed premises referred to in that section, any person under the age of twenty one years or any woman;

he shall be punished with fine which may extend to ten thousand rupees."

Amendment of
section 62

9. Section 62 with title in the Principle Act shall be substituted as follows, namely-

"Penalty for rendering denatured spirit fit for human consumption:

Whoever renders attempts to render fit for human consumption any spirit whether manufactured in India or not which has been denatured, or has in his possession any denatured spirit which has been rendered fit for human consumption or in respect of which any attempt has been made to render it so fit shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than six months, and which may extend to three years, and shall also be liable to fine of five thousand rupees which may extend to fifty thousand rupees.

Explanation— For the purpose of this section, it shall be presumed that any spirit which is proved to contain any quantity of any denaturant, is or contains or has been derived from denature spirit."

Amendment of
section 63

10. Section 63 with title in the Principle Act shall be substituted as follows, namely-

"Penalty for possession of intoxicant un-lawfully imported, etc.

Whoever, without lawful authority, has in his possession any quantity of any intoxicant knowing them same to have been unlawfully imported, transported or manufactured or knowing the prescribed duty not to have been paid thereon, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which shall not be less than five thousand rupees and which may extend to ten times or with both."

Amendment of
section 64

11. In section 64 with title in the Principle Act shall be substituted as follows, namely-

"Penalty of certain acts by licensee or his servant:

Whoever, being the holder of a licence, permit or pass granted under this Act or being in the employment of such holder and acting on his behalf-

(a) fails to produce such licence, permit or pass on the demand of any Excise Officer or of any other officer duly empowered to make such demand; or

(b) willfully does or omits to do anything in breach of any of the conditions of the licence, permit or pass, not otherwise provided in this Act;

(c) save in a case provided for by section 60, willfully contravenes any rule made under section 40;

shall for each such contravene be punished with fine which may extend to twenty thousand rupees."

Amendment of section 64A

12. Section 64 A with title in the Principle Act shall be substituted as follows, namely-

"Penalty for acculturation by licence vendor or manufacturer:

(1) Whoever, being the holder of a licence for the sale or manufacture of any intoxicant under this Act or a person in the employment of such holder, mixes or permits to be mixed with the intoxicant sold or manufactured by him any noxious drug or any improper ingredient likely to add to its actual or apparent intoxicating quality or strength or any Article prohibited by any rule made under the Act, when such mixture does not amount to an offence of adulteration under section 272 of the Indian Penal Code, shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than six months and which may extend to three years and also with fine which shall not be less than ten thousand rupees and which may extend to twenty thousand rupees.

(2) Whoever being the holder of a licence for the sale or manufacture of any intoxicant under this Act, or a person in the employment of such holder sells or keeps or exposes for sale as foreign liquor which he knows or has reason to believe to be country liquor shall be punished with imprisonment for a term which may extend to

three years and with fine which may extend to twenty thousand rupees :

Provided that the punishment shall not be less than -

(i) imprisonment for three months and fine of two hundred rupees for the first offence; and

imprisonment for six months and fine of five hundred rupees for each of the second or subsequent offences."

Amendment of section 65

13. Section 65 with title in the Principle Act shall be substituted as follows, namely-

"Penalty for consumption in chemists shop, etc.

(1) If any chemist, druggist, apothecary or keeper of dispensary allows any intoxicant which has not been *bona fide* medicated for medicinal purposes to be consumed on his business premises by any person not employed in his business, he shall be punished with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to twenty thousand rupees, or with both.

(2) If any person not employed as aforesaid consumes any such intoxicant on such premises, he shall be punished with fine which may extend to five thousand rupees."

**Amendment of
section 74**

14. Section 74 with title in the Principle Act shall be substituted as follows, namely-

"Compounding of offences:

(1) Any Excise Officer specially empowered by the State Government in that behalf may accept from any person whose licence, permit or pass is liable to be cancelled or suspended under section 34, or who is reasonably suspected of having committed an offence punishable under section 64 or section 68, a sum of money not exceeding One Lakh rupees in lieu of such cancellation or suspension or by way of composition for the offence, which may have been committed, as the case may be, and in all cases in which any property has been seized as liable to confiscation under this Act, may release the same on payment of the value thereof (as estimated by such officer).

(2) Any officers specially empowered by the State Government in that behalf may subject to any general or special order of the State Government compound, whether before or after the institution of the prosecution, any offence punishable under clause (a) of sub-section (1) of section 60 or section 63, where the quantity of the intoxicant involved does not exceed the quantity notified by the State Government in that behalf, or any offence punishable under sub-section (3) of section 60, on payment of such sum of money as composition fee as he think fit, which shall not be less than five thousand rupees ;

Provided that minimum amount of compound shall not be less than the fine mentioned in section 60(1), 60(3) and 63.

(3) On the payment by such person of sum of such money or such value or both, as the case may be, such person, if in custody, shall be set at liberty and all the property seized may be released and no proceeding shall be instituted or continued against such person in any criminal court. The acceptance of such sum of money by way of composition shall be deemed to amount of an acquittal and in no case shall any further proceeding be taken against such person or property with reference to the same act."

**Amendment of
section 74A**

15. Section 74A with title in the Principle Act shall be substituted as follows, namely-

"Imposition of penalty:

(1) If a holder of a licence, permit or pass granted under this Act or an employee of such holder contravenes any of the conditions of the licence, permit or pass or any rule made under this Act, any Excise Officer authorized by the State Government in this behalf may impose a penalty not exceeding (1,00,000/-) One Lakh rupees.

(2) No order imposing a penalty shall be made under sub-section (1) unless the holder of the licence, permit or pass or the employee concerned is given –

(a) a notice in writing informing him of the ground of which it is proposed to proceed under this section;

(b) a reasonable opportunity of making a representation in writing, within such time as may be specified in the notice, against such grounds; and

(c) a reasonable opportunity of being heard in the matter.

(3) No person on whom a penalty is imposed under sub-section (1) shall be liable to prosecution in respect of any offence under this Act on the same fact."

By Order,

Meena Tiwari,
Principal Secretary.

कारण और उद्देश्य

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (सं०प्रा० अधिनियम सं० 4 वर्ष 1910) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) में मादक भेषज, विक्रय, होटल, क्लब, रेस्टोरेंट, अधिसूचित स्थान, शराब परोसना, शराब की दुकान को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पुनः परिभाषित किया जाना आवश्यक है, जिस हेतु धारा-3 के खण्ड (12) व (16) में संशोधन तथा खण्ड-22 के उपरान्त 06 खण्ड(23),(24),(25),(26), (27) तथा (28) जोड़े जाने हैं। इसके अतिरिक्त अन्य परिणामिक संशोधन करने के लिए संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 17, 24क, 36, 41, 60, 61, 62, 63, 64, 64क, 65, 74, तथा 74क को संशोधित/प्रतिस्थापित किया जा रहा है। ये संशोधन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आवश्यक और अपरिहार्य हैं।

2- प्रस्तुत विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति करता है।